

II. सकल मांग

2009-10 की चौथी तिमाही में सकल मांग के चालकों में उल्लेखनीय बदलाव आया जो रिकवरी की प्रक्रिया के अधिकाधिक स्वयं धारणीय रहने के स्वरूप का संकेत देता है। निवेश मांग में सुधार में तेजी दिखाई दी, तथा पूंजीगत माल के उत्पादन की प्रवृत्तियों को देखते हुए 2010-11 में अब तक यह धारणीय प्रतीत होती है। निजी उपभोग मांग में मंदी बनी रही, हालांकि अग्रणी संकेतक हाल के महीनों में वृद्धि का संकेत देते हैं। सरकारी उपभोग मांग के अंशदान में काफी कमी आई है तथा राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया को दर्शाते हुए सरकारी व्यय से समर्थन में और कमी आने की आशा है। 2009-10 के दौरान निर्यातों की तुलना में आयात में आई तेज गिरावट के फलस्वरूप निवल निर्यात का सकारात्मक अंशदान देशी मांग बढ़ने पर 2010-11 में सामान्य स्वरूप में बदल जाएगा। इस प्रकार समग्र वृद्धि की संभावना मोटे तौर पर 2010-11 में निजी उपभोग तथा निवेश मांग की सुदृढ़ता द्वारा निरूपित होगी।

देशी मांग

II.1 वैश्विक संकट के संदर्भ में निजी उपभोग और निवेश मांग में कमी आई है, जिसकी वजह से मांग उत्प्रेरक मौद्रिक एवं राजकोषीय उपाय जरूरी हो गए हैं। मांग, विशेष तौर पर निजी निवेश मांग पक्ष से वृद्धि के स्वतः-धारणीय चालकों में 2009-10 की दूसरी छमाही में टर्नअराउंड दिखाई दिया, जिसने नीतिगत निकासी की शुरुआत को भी सुकर बनाया। निजी निवेश मांग में रिकवरी तथा निजी उपभोग मांग में सुदृढ़ वृद्धि बने रहने के साथ, मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण एवं राजकोषीय समेकन के जरिए एक ऐसा समष्टि आर्थिक

सारणी II.1 : सकल देशी उत्पाद का व्यय पक्ष (2004-05 की कीमतों पर)

मद	2008-09*	2009-10#	2008-09				2009-10			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वृद्धि दरें										
बाजार मूल्यों पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद कुल उपभोग व्यय	5.1	7.7	7.3	6.9	3.0	3.8	5.2	6.4	7.3	11.2
(i) निजी	8.3	5.3	7.7	7.6	13.2	4.6	4.7	9.6	4.8	2.6
(ii) सरकारी	6.8	4.3	8.4	7.6	6.4	5.1	2.9	6.4	5.3	2.6
सकल अचल पूंजी निर्माण	16.7	10.5	3.7	7.5	59.0	2.5	15.3	30.5	2.5	2.1
स्टॉक में बदलाव	4.0	7.2	6.5	7.3	-0.1	2.7	-0.7	1.6	8.8	17.7
निवल निर्यात	-61.2	5.9	-60.2	-60.3	-61.9	-62.2	-0.9	4.2	8.7	11.1
सापेक्ष हिस्सा										
कुल उपभोग व्यय	40.2	-9.7	31.1	101.0	77.7	-29.4	29.8	6.1	-0.3	-113.4
(i) निजी	70.9	69.4	71.8	69.4	75.2	67.5	71.4	71.5	73.4	62.3
(ii) सरकारी	59.5	57.6	61.3	60.1	61.5	55.4	59.9	60.1	60.4	51.1
सकल अचल पूंजी निर्माण	11.5	11.8	10.5	9.2	13.7	12.2	11.5	11.3	13.1	11.2
स्टॉक में बदलाव	32.9	32.8	33.0	34.8	31.5	32.7	31.2	33.2	31.9	34.6
निवल निर्यात	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3
	-6.1	-5.1	-5.2	-8.8	-7.3	-3.5	-6.5	-8.7	-6.7	0.4

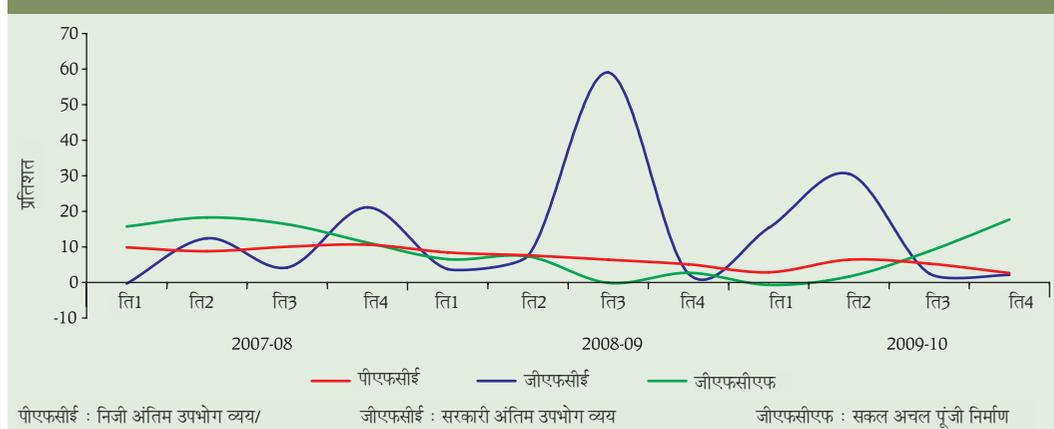
*: त्वरित अनुमान # : संशोधित अनुमान.

माहौल बनेगा जो उच्च वृद्धि को बनाए रखने में सहायक होगा।

II.2 सकल मांग में उभर रही प्रवृत्तियां वृद्धि की गति के प्रमुख चालकों तथा मध्यावधि में उनकी धारणीयता के बारे में उपयोगी आंतरिक जानकारी उपलब्ध कराती हैं। निजी उपभोग मांग 2008-09 के 6.8 प्रतिशत से

कम होकर 2009-10 में 4.3 प्रतिशत रह गया, जो एक ओर समग्र आर्थिक मंदी के मंदकारी प्रभाव को तथा दूसरी ओर कम कृषि उत्पादन एवं उच्च खाद्य मूल्यों को दर्शाता है। 2009-10 की चौथी तिमाही में निजी उपभोग मांग में आई मंदी विशेष रूप से तीव्र थी (सारणी II.1 और चार्ट II.1)।

चार्ट II.1 : देशी मांग के प्रमुख घटकों की वृद्धि दर



II.3 सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, जो 2008-09 की तीसरी तिमाही में वृद्धि के प्रमुख चालक के रूप में उभरा है, में 2009-10 की तीसरी तिमाही से उल्लेखनीय कमी आनी शुरू हो गई। सरकारी उपभोग व्यय में मंदी 2009-10 की चौथी तिमाही में बनी रही, जो संकट प्रेरित राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों के कारण पिछले साल की दूसरी छमाही के उच्च आधार को दर्शाता है। निजी और सरकारी दोनों तरह के उपभोग मांग में मंद वृद्धि के कारण 2009-10 की चौथी तिमाही में सकल मांग में वृद्धि के प्रति उनके अपने अंशदान में कमी आई (चार्ट II.2)।

II.4 2009-10 की चौथी तिमाही में 17.7 प्रतिशत पर सकल अचल पूंजी निर्माण में साल-दर-साल वृद्धि में उल्लेखनीय तेजी दिखाई दी। फलस्वरूप, वृद्धि के प्रति निवेश मांग का अंशदान काफी सुधर कर पिछली तिमाही के 38.0 प्रतिशत की तुलना में 2009-10 की चौथी तिमाही में 51.5 प्रतिशत हो गया। निवेश मांग में वृद्धि समग्र व्यावसायिक और निवेश माहौल में सुधार तथा मांग में प्रत्याशित उछाल को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि के इरादे को दर्शाती है। स्थिर निवेश

कार्यकलाप के अलावा 2009-10 की तीसरी और चौथी तिमाहियों के दौरान इनवेंटरी में तीव्र वृद्धि के संकेत मिले।

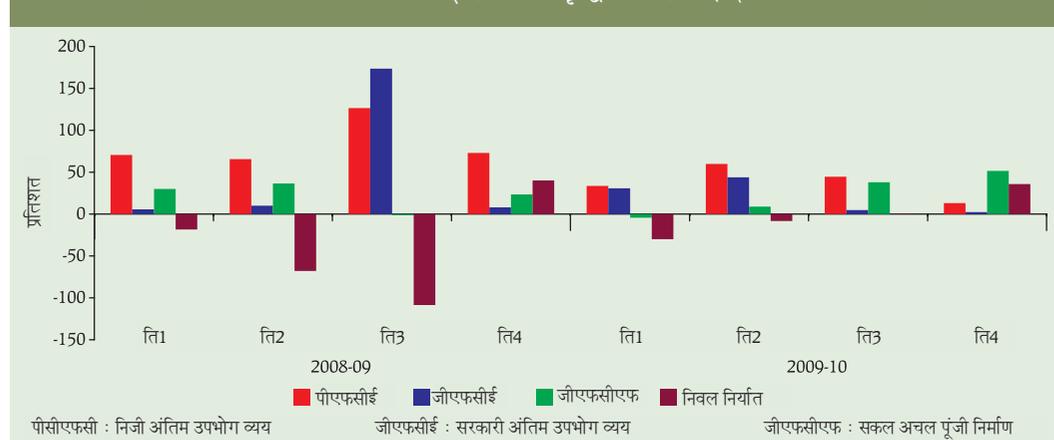
राजकोषीय नीति के माध्यम से मांग प्रबंधन

केन्द्र सरकार के वित्त : 2009-10 और 2010-11

II.5 सुधार की गति को समर्थन देने की दृष्टि से, राजकोषीय नीति का विस्तारकारी रुख 2009-10 के दौरान जारी रहा। इसे दर्शाते हुए, राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा पिछले साल (संशोधित अनुमान की तुलना में बढ़ गया (सारणी II.2)।

II.6 अप्रत्यक्ष कर कटौतियों को आंशिक रूप से वापस किए जाने तथा योजनेतर व्यय की वृद्धि के संकुचन के माध्यम से राजकोषीय उत्प्रेरक उपायों से क्रमिक रूप से निकलने के साथ, केंद्र सरकार ने 2010-11 में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया शुरू की। जीडीपी में प्रत्याशित उच्चतर वृद्धि के साथ इन उपायों से, राजस्व घाटा तथा सकल राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 2010-11 (बअ) के दौरान कम किया जाना परिकल्पित है।

चार्ट II.2 : मांग पक्ष से जीडीपी वृद्धि में भारत अंशदान



सारणी II.2: मुख्य राजकोषीय संकेतक				
(सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत)				
वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5
केंद्र				
2008-09 (वास्तविक)	2.6	4.5	6.0	56.7
2009-10 संअ	3.1	5.3	6.6	56.4
2010-11 बअ	1.9	4.0	5.5	56.9
राज्य*				
2008-09 (वास्तविक)	0.6	-0.2	2.4	26.2
2009-10 संअ	1.7	1.0	3.6	26.3
2010-11 बअ	1.2	0.6	3.0	-
संयुक्त				
2008-09 (वास्तविक)	3.4	4.4	8.5	71.6
2009-10 संअ	4.9	6.2	10.1	72.4
2010-11 बअ	3.2	4.6	8.5	-
संअ : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान.				
* : 24 राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित.				
- : उपलब्ध नहीं.				
नोट: घाटा मानकों के सामने घटाव का संकेत अधिशेष को दर्शाता है।				

II.7 2010-11 के केंद्रीय बजट में परिकल्पित घाटा संकेतकों में सुधार कई कारकों के संयुक्त प्रभाव के माध्यम से आना है, ये कारक इस प्रकार हैं: उच्चतर राजस्व प्राप्तियां, विनिवेश आगम राशियों में वृद्धि, तथा राजस्व व्यय, विशेष रूप से योजनेतर घटक, की वृद्धि में कटौती (सारणी II.3)। 3जी/बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम नीलामियों से 1,06,262 करोड़ रुपए के राजस्व की

वसूली हुई, जो 2010-11 के केंद्रीय बजट में अनुमानित 35,000 करोड़ रुपए की राशि के तिगुने से अधिक है। फलस्वरूप, करेतर राजस्व प्राप्तियां बजट स्तर से 48 प्रतिशत बढ़ने की आशा है। व्यय बढ़ाने के लिए यदि इस अतिरिक्त जुटाए गए संसाधन का उपयोग नहीं किया गया तो इससे 2010-11 के बजट अनुमान में की गई परिकल्पना की तुलना में राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा दोनों में 1.0 प्रतिशत अंक की अतिरिक्त कमी आएगी, तथा इस प्रकार निजी निवेश की गुंजाइश और बढ़ जाएगी। जून 2010 में पेट्रोल की कीमतों को अविनियमित करने तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में ऊर्ध्वमुखी संशोधन करने के बारे में लिए गए निर्णय से भी मध्यावधि में राजकोषीय धारणीयता में अंशदान देने के अलावा राजकोषीय स्थिति पर दबाव को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। 2010-11 के केंद्रीय बजट में घोषित कुछ कर उपाय, यथा आय कर स्लेब में वृद्धि और अप्रत्यक्ष कर उपाय यथा, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर से छूट का निजी उपभोग और निवेश मांग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अप्रैल-जून 2010 के दौरान प्रत्यक्ष कर

सारणी II.3: केन्द्र सरकार के वित्त						
पद	वृद्धि दर (प्रतिशत)			जीडीपी की तुलना में प्रतिशत		
	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	24.0	15.6	8.5	15.9	16.4	16.0
2. राजस्व व्यय	33.5	14.2	5.8	14.2	14.5	13.8
3. पूंजीगत व्यय	-23.7*	27.8	30.2	1.6	1.8	2.2
4. योजनेतर व्यय	19.9	16.0	4.1	10.9	11.3	10.6
5. योजना व्यय	34.2	14.5	18.4	4.9	5.1	5.4
6. राजस्व प्राप्तियां	-0.3	6.9	18.2	9.7	9.3	9.8
i) कर राजस्व (निवल)	0.9	4.9	14.8	8.0	7.5	7.7
ii) गैर कर राजस्व	-5.3	15.7	32.0	1.7	1.8	2.1
संअ : संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान.						
* : तेज गिरावट अनिवार्य रूप से भारत सरकार द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की हिस्सेदारी के अधिग्रहण के कारण पिछले वर्ष (2007-08) के उच्चतर आधार को दर्शाती है।						

वसूलियों में सुदृढ़ वृद्धि दर्ज की गई, जो अन्य बातों के साथ-साथ आर्थिक कामकाज में उछाल को दर्शाता है।

II.8 अतिरिक्त पूंजी निवेश करने तथा सकल देशी मांग बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, राज्यों को 2008-09 में उनके जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत तक तथा 2009-10 में और 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई। फलस्वरूप 2009-10 (संअ) में राज्य सरकारों के समग्र व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप घाटा बढ़ गया। 2010-11 के बजट प्रलेखों के अनुसार, राज्य सरकारों ने राजकोषीय समेकन¹ की प्रक्रिया आरंभ की है। यह आशा है कि राजस्व व्यय की वृद्धि 2009-10 (संअ) के 25.2 प्रतिशत से काफी कम करके 2010-11 (बअ) में 9.6 प्रतिशत करने के माध्यम से घाटा संकेतकों में सुधार लाया जाएगा, जबकि उसी अवधि में पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि 11.4 प्रतिशत से कम करके 3.8 प्रतिशत किए जाने से भी इस प्रक्रिया में मदद मिलने की आशा है। इसकी अनुपूर्ति 2010-11 (बअ) में राज्यों के अपने कर राजस्व में 16.6 प्रतिशत की वृद्धि करके

तथा केंद्रीय करों में उनके हिस्से में 19.9 प्रतिशत की वृद्धि करके की जाएगी। फलस्वरूप, राज्यों का राजस्व घाटा और सकल राजकोषीय घाटा 2010-11 (बअ) में कम रहने का बजट अनुमान है।

संयुक्त राजकोषीय स्थिति

II.9 केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों का विस्तारकारी राजकोषीय रुख जारी रहना दर्शाते हुए, क्रमिक राजस्व घाटा बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गया, जबकि सकल राजकोषीय घाटा बढ़कर 2009-10 में जीडीपी का 10.1 प्रतिशत हो गया। 2010-11 में केंद्र और राज्य दोनों द्वारा राजकोषीय समेकन का मार्ग परिकल्पित किए जाने के कारण संयुक्त वित्त में काफी सुधार आने की संभावना है (सारणी II.4)।

कंपनियों का कार्य-निष्पादन

II.10 कंपनियों की बिक्री संबंधी आंकड़ों से भी समग्र आर्थिक कार्यकलाप में उछाल स्पष्ट दिखाई देता था। 2009-10 की चौथी तिमाही में, चुनिंदा गैर-वित्तीय गैर-सरकारी सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री में लगभग 29

सारणी II.4: संयुक्त वित्त

मद	वृद्धि दर (प्रतिशत)			सकल देशी उत्पाद का प्रतिशत		
	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	20.4	19.6	8.4	28.4	30.4	29.6
2. राजस्व व्यय	25.7	20.0	7.4	24.2	25.9	25.0
3. पूंजीगत व्यय	-3.0	17.4	13.9	4.3	4.5	4.6
4. गैर विकास व्यय	7.1	22.5	11.2	11.3	12.4	12.4
5. विकास व्यय	31.5	17.8	6.1	16.8	17.7	16.8
6. राजस्व प्राप्तियां	3.9	11.4	15.6	19.8	19.7	20.5
i) कर राजस्व	5.2	7.5	16.3	16.6	15.9	16.7
ii) गैर कर राजस्व	-2.6	31.1	12.3	3.2	3.8	3.8

संअ: संशोधित अनुमान. बअ : बजट अनुमान.

नोट : केन्द्र सरकार और 24 राज्य सरकारों से संबंधित आंकड़े।

¹ चौबीस राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों पर आधारित।

सारणी II.5: गैर सरकारी गैर वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों का कार्य-निष्पादन

(प्रतिशत में वृद्धि दर/ अनुपात)

मद	2008-09	2009-10	2008-09				2009-10			
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
बिक्री	17.2	11.7	29.3	31.8	9.5	1.9	-0.9	0.1	22.5	29.1
अन्य आय *	6.6	6.3	-8.4	-0.6	-4.8	39.4	50.2	6.0	7.4	10.3
व्यय	19.5	9.6	33.5	37.5	12.6	-0.5	-4.4	-2.5	20.6	30.7
मूल्यहास प्राक्धान	17.4	22.2	15.3	16.5	16.8	19.6	21.5	20.7	21.6	20.1
सकल लाभ	-4.2	24.9	11.9	8.7	-26.7	-8.8	5.8	10.9	60.0	36.7
ब्याज भुगतान	57.3	-3.2	58.1	85.3	62.9	36.5	3.7	-1.0	-12.3	-2.9
कर के बाद लाभ	-18.4	28.8	6.9	-2.6	-53.4	-19.9	5.5	12.0	99.3	44.0
चुनिंदा अनुपात										
बिक्री के प्रति स्टॉक में बदलाव #	0.4	1.0	2.9	2.2	-1.7	-1.8	0.6	2.3	0.8	1.1
बिक्री के प्रति सकल लाभ	13.3	14.8	14.5	13.5	11.0	13.7	15.7	14.9	14.3	14.6
बिक्री के प्रति करोत्तर लाभ	8.1	9.4	9.7	8.6	5.3	8.1	10.2	9.4	8.8	9.0
बिक्री के प्रति ब्याज	3.1	2.7	2.4	2.9	3.8	3.2	2.8	3.1	2.7	2.4
सकल लाभ के प्रति ब्याज	23.6	18.2	16.8	21.5	34.6	23.3	18.0	20.5	19.1	16.6
ब्याज कवरेज (गुना)	4.2	5.5	6.0	4.6	2.9	4.3	5.6	4.9	5.2	6.0

: स्पष्ट रूप से व्यापारार्थी स्टॉक में बदलाव सूचित करने वाली कंपनियों के लिए।

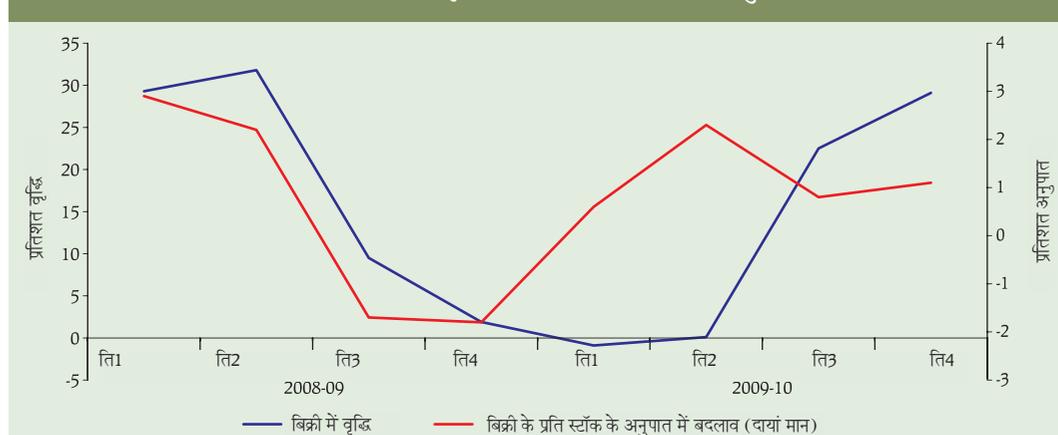
नोट : 1. वृद्धि दरें वर्ष सामान्य सेट वाली कंपनियों के लिए साल-दर-साल प्रतिशत परिवर्तन हैं।

2. प्रत्येक अवधि में शामिल किए गए नमूने की संख्या और संरचना में अंतर होने के कारण हो सकता है कि तिमाही आंकड़े वार्षिक आंकड़ों से मेल न खाएं।

प्रतिशत की साल-दर-साल बढ़ोतरी हुई, जो पिछली छः तिमाहियों की सर्वाधिक बिक्री है (सारणी II.5)। निवल लाभ में भी पिछले साल की तदनु रूप अवधि में हुई तीव्र गिरावट के विपरीत 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मोटे तौर पर विनिर्माण कंपनियों से आई। राजस्व वसूली में सुधार न्यून आधार के अलावा आर्थिक

कार्यकलाप में सुदृढ़ रिकवरी तथा पण्य की बढ़ती कीमतों को दर्शाता है। लाभ मार्जिन में भी अन्य आय में वृद्धि तथा ब्याज के बहिर्गम में गिरावट का समर्थन बना रहा। 2009-10 की चौथी तिमाही में बिक्री और इन्वेंटरी दोनों की मांग बढ़ी है जो औद्योगिक कार्यकलाप में वृद्धि का संकेत है (चार्ट II.3)।

चार्ट II.3 : बिक्री में वृद्धि और बिक्री के प्रति स्टॉक के अनुपात में बदलाव



II.11 बाद में, 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों में मौसमी तौर पर समायोजित बिक्री में सुधार हुआ परंतु चौथी तिमाही में इसमें गिरावट आई। प्रमुख बैंकों / वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त परियोजना वित्त संबंधी आंकड़े निजी कंपनी क्षेत्र के निवेश संबंधी इरादों में अच्छी दृढ़ता सुझाते हैं।

बाह्य मांग

II.12 निवल निर्यात (स्थिर कीमतों पर माल और सेवाओं का) ने 2008-09 के लगभग 36.2 प्रतिशत के ऋणात्मक अंशदान की तुलना में 2009-10 में मांग पक्ष में जीडीपी वृद्धि में 7.8 प्रतिशत का सकारात्मक अंशदान किया। पहले की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत निवल निर्यातों का सकारात्मक अंशदान वर्ष के दौरान निर्यातों की तुलना में आयातों में अपेक्षाकृत अधिक गिरावट से उत्पन्न हुआ। 2009-10 की चौथी तिमाही में निवल निर्यातों के अंशदान में और वृद्धि हुई क्योंकि निर्यात में 14.2 प्रतिशत की

वृद्धि हुई जबकि आयातों में 3.7 प्रतिशत की गिरावट आई (देखें चार्ट II.2)। अप्रैल-जून 2010 के वाणिज्य वस्तु व्यापार संबंधी आंकड़े निर्यातों की तुलना में आयातों में उच्चतर वृद्धि सुझाते हैं। इस प्रकार, निवल निर्यातों का सकारात्मक अंशदान 2010-11 में बदल जाने की आशा है। बाह्य मांग संबंधी स्थितियों पर ब्यौरेवार चर्चा अध्याय III में की गयी है।

II.13 संक्षेप में, निवेश मांग में जबर्दस्त टर्नअराउंड दिखाई दिया, तथा पूंजीगत माल की उत्पादन की प्रवृत्तियों, तेल से इतर आयात और कारपोरेट लाभ को देखते हुए इसके बने रहने की आशा है। जहां 2009-10 में निजी उपभोग मांग में मंदी थी, वहीं हाल के महीनों में कंपनियों की बिक्री, उपभोक्ता टिकाऊ और गैर टिकाऊ माल के उत्पादन तथा आटोमोबाइल की बिक्री की प्रवृत्तियां निजी उपभोग मांग में उल्लेखनीय उछाल दर्शाती हैं। तथापि सकल मांग के प्रति निवल निर्यात का अंशदान ऋणात्मक हो जाएगा जो उच्चतर आयात मांग को दर्शाता है।